

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के सर्वेक्षण की समस्याओं के निराकरण पर दिनांक 25.02.2013 को मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में होने वाली VC की कार्यवाही :-

1. अधिकांश जिलों में प्रगणन का कार्य पूर्णता के निकट है । पूर्वी चम्पारण, सीतामढी, मधुबनी एवं पटना में प्रगणन की धीमी प्रगति पर धिन्ता व्यक्त की गई तथा इन जिलों को प्रगणन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया ।
2. जिन जिलों में प्रगणन कार्य समाप्ति के निकट है वहाँ Supervisory तथा Verification and Correction Module पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है ।
3. Supervisory Module का अपलोडेड डाटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ की कई जिले जिन्होने शतप्रतिशत प्रगणन कार्य पूर्ण कर लिया है उनकी प्रगति शून्य दर्शायी जा रही है । इससे प्रतीत होता है कि Supervisory Module का डाटा, ECIL के द्वारा ससमय अपलोड नहीं किया जा रहा है । इस संबंध में ECIL के प्रतिनिधि को ससमय डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया ।
4. Supervisory Module के बाद भी PTG, Manual Scavenger and Bonded Labour बड़ी संख्या में परिलक्षित हो रहे हैं । इसपर Verification and Correction Module के दौरान विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।
5. रोहतास तथा बक्सर जिले के द्वारा DEOs का Payment का मुद्दा उठाया गया, ECIL के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की आज दिनांक 25.02.2013 को हैदराबाद में Vyamtech के प्रतिनिधि के साथ बैठक की जा रही है, जिसमें DEDs के पारिश्रमिक का भुगतान ससमय सुनिश्चित कराने की कार्रवाई की जा रही है ।
6. कुछ जिलों यथा - मधेपुरा, सहरसा एवं मुंगेर के द्वारा Draft list Publication की अनुमति मांगी गयी ECIL के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि अभी MoRD के द्वारा JPG degitization का कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण सभी राज्यों के Draft Publication पर रोक लगा दी गयी है । प्रगणन कार्य के गुणवत्ता की जाँच हेतु कुछ चार्ज सेंटरों का प्रारूप प्रकाशन कराये जाने हेतु MoRD की सहमति के पश्चात जिलों को दिशा- निर्देश जारी किये जायेंगे ।

(NO 6/3/13)
(संजय कृष्ण)

विशेष कार्य पदाधिकारी ।
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापक : 141169

पटना दिनांक 6/3/13

गोवि०-5/सा०आ०जन०(पी.सी.)-103-12/2012

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार सरकार के प्रधान आप्त सचिव/ सभी जिला पदाधिकारी/ ECIL प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(NO 6/3/13)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।